



## उत्तराखण्ड में राज्य सहायता मशिन पर क्षेत्रीय कार्यशाला

### चर्चा में क्यों?

[नीतिआयोग](#) ने उत्तराखण्ड [सशक्तीकरण एवं परिवर्तन संस्थान \(सेतु\) आयोग](#) के सहयोग से देहरादून में [राज्य सहायता मशिन \(SSM\)](#) के अंतर्गत एक दृष्टिपूर्ण क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की।

### मुख्य बंदि

- क्षेत्रीय कार्यशाला के बारे में:
  - यह कार्यशाला [राज्य सहायता मशिन \(SSM\)](#) के अंतर्गत आयोजित शृंखला की पहली कार्यशाला थी, जिसका उद्देश्य [राज्य परिवर्तन संस्थानों \(SIT\)](#) के माध्यम से नीतिआयोग तथा राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के बीच संरचित सहयोग को बढ़ावा देना था।
  - कार्यशाला का उद्देश्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एक साथ लाकर SSM पहल पर अनुभव साझा करना, सहकर्मी शिक्षा को बढ़ावा देना और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये सहयोग बढ़ाना था।
  - इसमें राज्य के विकास को गति देने तथा राज्य के वज़िन को आकार देने में SIT की भूमिका पर प्रकाश डाला गया।
- राज्य सहायता मशिन (SSM):
  - इस मशिन के अंतर्गत, नीतिआयोग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को क्षमता निर्माण तथा राज्य परिवर्तन संस्थानों (SIT) की स्थापना में सहायता प्रदान करता है।
  - इसका उद्देश्य राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप वर्ष 2047 तक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को उनके सामाजिक-आर्थिक विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करना है।
    - इस मशिन को 2022-23 से 2024-25 की अवधि के लिये 237.5 करोड़ रुपए के कुल परियोजना के साथ मंजूरी प्रदान की गई है।
  - मशिन के क्रियान्वयन हेतु नीतिआयोग में एक राज्य आर्थिक एवं परिवर्तन इकाई (सेतु) का गठन किया गया है।
    - संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी (मशिन निदेशक) की अध्यक्षता वाली इस इकाई में निदेशक, सहायक निदेशक, नवाचार प्रमुख तथा युवा पेशेवरों की एक टीम सम्मिलित है।
  - SSM, [सतत विकास लक्ष्यों \(SDG\)](#) के स्थानीयकरण पर्याप्तों को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध होगा, जिससे [बहुआयामी गरीबी](#) को कम करने में मदद मिलेगी।

# नीति आयोग

(राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था)

## इतिहास- योजना आयोग

वर्ष 1950 में निवेश संबंधी गतिविधियों को निर्देशित करने हेतु स्थापित

1 जनवरी, 2015 को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित

### नीति आयोग की संरचना

#### अध्यक्ष

प्रधानमंत्री

#### शासी मंत्रिपरिषद्

CMS (राज्य) और उपराज्यपाल (VTS)

#### क्षेत्रीय परिषदें

आवश्यकतानुसार गठित, जिसमें क्षेत्र के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल होते हैं

#### सदस्य

पूर्णकालिक

#### अंशकालिक सदस्य

अधिकतम 2, क्रमिक, महत्वपूर्ण संस्थानों से

#### पदेन सदस्य

अधिकतम 4 मंत्रिपरिषद् से, प्रधानमंत्री द्वारा नामित

#### विशेष आमंत्रितकर्ता

अनुभवी, विशेषज्ञ, डोमेन ज्ञान वाले अभ्यासकर्ता

#### मुख्य कार्यकारी अधिकारी

निश्चित कार्यकाल के लिये प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त (सचिव रैंक)

#### सचिवालय

आवश्यकतानुसार

## उद्देश्य

- सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना
- विश्वसनीय योजनाओं के निर्माण हेतु तंत्र विकसित करना (ग्रामीण स्तर पर)
- आर्थिक रणनीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी हितों को बढ़ावा
- सुभेद्य वर्गों पर विशेष ध्यान
- प्रमुख हितधारकों, नेशनल-इंटरनेशनल थिंक टैंक, शोध संस्थानों के बीच साझेदारी के लिये सलाह और प्रोत्साहन प्रदान करना
- ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता सहायता प्रणाली का निर्माण
- अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु मंच प्रदान करना
- अत्याधुनिक संसाधन केंद्र (state-of-the-art Resource Centre) बनाए रखना

### नीति आयोग बनाम योजना आयोग

नीति आयोग	योजना आयोग
यह एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है।	यह गैर-संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता था।
इसमें व्यापक विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं।	इसमें सीमित विशेषज्ञता थी।
प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिवों को CEO के रूप में जाना जाता है।	सचिवों को सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाता था।
यह योजना के 'बॉटम-अप' दृष्टिकोण पर केंद्रित है।	इसने 'टॉप-डाउन' दृष्टिकोण का अनुसरण किया।
इसके पास नीतियाँ लागू करने का अधिकार नहीं है।	राज्यों पर नीतियों को लागू किया और अनुमोदित परियोजनाओं के साथ धन का आवंटन किया।
इसके पास निधि आवंटित करने का अधिकार नहीं है, जो वित्त मंत्री में निहित है।	इसे मंत्रालयों और राज्य सरकारों को निधि आवंटित करने का अधिकार था।

## प्रमुख पहलें

- सतत् विकास लक्ष्य (SDG) इंडिया इंडेक्स
- अटल इनोवेशन मिशन
- ई-अमृत पोर्टल (इलेक्ट्रिक वाहन)
- सुशासन सूचकांक
- भारत नवाचार सूचकांक
- आकांक्षी जिला कार्यक्रम
- 'मेथनॉल अर्थव्यवस्था' कार्यक्रम

## प्रमुख पहलें

- राज्यों को विवेकाधीन निधि प्रदान करने का अधिकार नहीं
- केवल एक सलाहकार निकाय
- निजी या सार्वजनिक निवेश को प्रभावित करने में कोई भूमिका नहीं
- संगठन का राजनीतिकरण
- सकारात्मक बदलाव लाने के लिये अपेक्षित शक्ति (Requisite Power) का अभाव



Drishti IAS